इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स

सरकार ने इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स शुरू करने के बारे में एक घोषणा की है, जिसके लिए सबसे पहले वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि ''भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह मशविरे के साथ, मैं ऐसे निवेश दस्तावेज शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जो मुद्रास्फीति से बचत की संरक्षा कर सकेंगे, विशेषकर निर्धन और मध्यम वर्ग की बचत पर मुद्रास्फीति का असर नहीं पड़ेगा। इन दस्तावेज को इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स अथवा इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्रों का नाम दिया जा सकता है।

बढ़ती महंगाई से बचत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स जारी करेगा। इन वित्तीय दस्तावेज का लक्ष्य बचत को प्रोत्साहित करना और निवेशकों में सोने का मोह कम करना है। रिजर्व बैंक सोने के प्रति आकर्षण कम करने में कितना सफल होगा, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बांड शुरू होने से भारतीय निवेशकों को अपनी बचत को मुद्रास्फीति के असर से बचाने में जरूर मदद मिलेगी।

2. इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड क्या है?

(i) इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स ऐसे बांड हैं जिनमें मूलधन को महंगाई के साथ संबद्ध (इंडेक्स) किया जाता है। इस प्रकार उनका डिजाइन किसी निवेश को मुद्रास्फीति के जोखिम से बचाने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रकार का प्रथम इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड 1780 में मैसाचुसेट्स बे कंपनी द्वारा जारी किया गया था। 1981 में ब्रिटिश सरकार द्वारा महंगाई से जुड़े बांड शुरू करने के बाद बाजार में नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी हुई थी। 2008 तक ब्रिटिश सरकार ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स जारी किए। इन्फ्लेशन–लिंक्ड बाजार में मुख्य रूप से सार्वभौम बांड्स शामिल हैं, और प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी इन्फ्लेशन–लिंक्ड बांड्स की बाजार में मामूली हिस्सेदारी है।

(ii) ढांचा

इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स एक सावधिक कूपन अदा करते हैं, जो मंहगाई सूचकांक उत्पाद और न्यूनतम कूपन दर के बराबर होता है। कूपन भुगतानों, महंगाई का वर्गीकरण और वास्तविक ब्याजदरों के बीच संबंध फिशर इक्वेशन के जरिए निर्दिष्ट किया जाता है। कूपन भुगतान में बढ़ोतरी महंगाई की संभावनाओं, वास्तविक दरों या दोनों के परिणामस्वरूप होती है।

कुछ बांड्स के मामले में, जैसे सीरीज–1 सेविंग्स बांड्स (अमरीका), ब्याज की दर महंगाई के अनुसार समायोजित होती है।

अन्य बांड्स के लिए, जैसे ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टिड सिक्योरिटीज (टिप्स) के मामले में बांड का अंतर निहित सिद्धांत बदलता रहता है, जिसकी परिणति समान दर से गुणा करने के बाद अधिक ब्याज प्राप्ति के रूप में होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी बांड का वार्षिक कूपन पांच प्रतिशत हो और बांड का अंतर्निहित सिद्धांत 100 यूनिटें हों, तो वार्षिक भुगतान पांच यूनिट होगा। यदि महंगाई सूचकांक में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाए तो बांड का मूलधन बढ़कर 110 यूनिट हो जाएगा। कूपन दर पांच प्रतिशत रहेगी, जिसे ब्याज भुगतान 110 x 5 प्रतिशत= 5.5 यूनिटें होगा।

(iii) वास्तविक प्राप्ति

किसी बांड की वास्तविक प्राप्ति उसकी वार्षिक वृद्धि दर होती है, जिसमें से उसी अवधि के लिए मुद्रास्फीति की दर कम की जाती है। यह गणना न्यूनतम बांड के मामले में सैद्धांतिक दृष्टि से अक्सर जटिल होती है, क्योंकि ऐसे बांड से प्राप्तियां न्यूनतम शर्तों पर भविष्य की अवधियों के लिए निर्दिष्ट होती है, जबकि गणना के समय मुद्रास्फीति की दर उस अवधि के लिए अज्ञात होती है। किंतु टिप्स जैसे इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स के मामले में, बांड से प्राप्ति मुद्रास्फीति में वृद्धि की दर के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है, अतः एक मानक बांड गणना फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए उस पर वास्तविक प्राप्ति की गणना आसानी से की जा सकती है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन–लिंक्ड बांड्स शुरू करने की घोषणा की है। यह बांड निवेश का अद्यतन दस्तावेज है। जो लोग मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम से अपने निवेश के संरक्षण के लिए सोने की तरफ दौड़ते हैं उनके लिए इन बांडों से नए आयाम खुले हैं। लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन–इन्डेक्स्ड बांड्स (आईआईबीज) जारी करने का फैसला किया है, जो अमरीका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के बाजारों में पहले से लोकप्रिय हैं। निवेश के ये दस्तावेज मुद्रास्फीति के युग में निवेशकों की पूंजी और ब्याज का संरक्षण करने में मददगार सिद्ध होंगे।

ये ऐसे बांड हैं जो एक वास्तविक रिटर्न (लाभ), अथवा मुद्रास्फीति की दर से अधिक दर पर निवेश लाभ की गारंटी देते हैं। ये बांड मुद्रास्फीति की दर के साथ सूचीबद्ध होते हैं, अथवा सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे बांड हैं जिनकी पूंजी वृद्धि और कूपन भुगतान मुद्रास्फीति की दरों के साथ जुड़ा होता है।

आमतौर पर देशों द्वारा ऐसे बांड उस समय निवेशकों की पूंजी की रक्षा के लिए जारी किए जाते हैं जब मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची होती है। सुरक्षित लाभ, जो मुद्रास्फीति के स्तर से अधिक होता है, चाहने वाले निवेशक इन बांडों के विकल्प को अपना सकते हैं। रिजर्व बैंक और भारत सरकार का एक अन्य उद्देश्य परिवारों को सोना खरीदने की बजाय वित्तीय दस्तावेज में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। ये बांड भारतीय उपभोक्ताओं को महंगाई के खिलाफ अनुकूल संरक्षण प्रदान करते हैं।

आईआईबी मुद्रास्फीति–विरोधी नीतियों की विश्वसनीयता भी बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ने के बारे में अनुमान व्यक्त करते हैं और धन निवेश के लिए अतिरिक्त आयाम प्रदान करते हैं और साथ ही सरकार के प्रतिभूति बाजार का विस्तार भी करते हैं।

इन बांडों का आकार और परिपक्वता अवधि क्या होगी?

भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के साथ सलाह मशविरा करके बांड्स की शुरूआत करेगा। आईआईबी जारी करते समय बेंचमार्क के अनुसार परिपक्वता अवधि के विभिन्न बिंदु लक्षित किए जाएंगे। प्रारंभ में ये बांड 10 वर्ष के लिए जारी किए जाएंगे। आईआईबी की प्रत्येक खेप रु. 1000 रु. 2000 करोड़ की होगी और इश्यू की कुल राशि वर्ष 2013–14 में रु. 12000 रु. 15000 रु. के बीच होगी।

(स्रोत : समाचार पत्र और एजेंसियां)